



सबसे तेज प्रयागराज

सब पर नजर, सटीक खबर

नगर संस्करण



sabsetejprj2023@gmail.com सोमवार , 27 जुलाई 2026

वर्ष: 04, अंक: 127 पृष्ठ: 08, मूल्य: 2 रु.

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

परीक्षा सुधार: नंदन नीलेकणि की अगुवाई में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स

पेपरलीक रोकने के लिए आज कठोर कानून लाएंगे, परीक्षा सुधार के लिए हाईपावर टास्क फोर्स बनाई

नई दिल्ली

पीएम मोदी ने रविवार शाम 7 बजे के करीब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। मोदी ने कहा- फ्रेंड्स स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वे जेलों में सड़ रहे हैं।

हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम कल संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो।

इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणि जी के नेतृत्व में एक हाईपावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।

23 जुलाई: पहला वीडियो जारी किया

23 जुलाई की रात 12 बजे हैंडल पर पोस्ट किए गए 2.56 मिनट के वीडियो में मोदी ने कहा- पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले दस महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों



नारायण मूर्ति के साथ मिलकर की इंफोसिस की शुरूआत

साल 1978 में उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से होती है। इन दोनों की मुलाकात के बाद ही इंफोसिस की शुरूआत हुई। ये 80 का दशक था। उस दौरान आज के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप काफी अलग था। इस दौर में किसी स्टार्टअप का ग्रो करना काफी मुश्किल काम था। करीब 10 वर्षों तक इंफोसिस काफी मुश्किल हालातों में चलती रही। वहीं साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए मेजर रिफॉर्म

का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।

मनमोहन सिंह ने दी थी 'आधार' प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी

नंदन नीलेकणि की इसी काबिलियत को देखते हुए साल 2009 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें यूआईडीएआई प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने के लिए आमंत्रित किया। नंदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। डिजिटल इंडिया को आकार

ने मानों इंफोसिस को एक नया रास्ता दे दिया हो।

साल 1992 में इस कंपनी ने

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया

उन्होंने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया

देने में यूआईडीएआई एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आज दुनियाभर में आधार को सबसे बड़े बायोमीट्रिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। आधार कार्ड आने के बाद आज कई सरकारी सेवाओं को बेहद ही कम समय में लोगों तक पहुंचाना संभव हो पाया है।

अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में लॉन्च किया। इसके बाद दुनिया भर में कई बड़ी कंपनियां

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ा है।

इंफोसिस द्वारा बनाए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने लगीं। यही नहीं इस दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी तेजी से बढ़ने लगा था। साल 1999 में इंफोसिस पर लिस्ट होने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। लिस्ट होने के तुरंत बाद इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक अरब डॉलर के बँचमार्क को पार कर दिया। साल 2002 में नंदन नीलेकणि को कंपनी का सीईओ बनाया गया।

24 जुलाई: दूसरा वीडियो मोदी बोले- वीडियो पर सकारात्मक सुझाव के लिए शुक्रिया

कौन हैं नंदन नीलेकणि?



नंदन नीलेकणि का शुरूआती जीवन?

नंदन नीलेकणि का जन्म देश के आईटी हब कहे जाने वाले बंगलुरु शहर में 2 जून, 1955 को हुआ था। इनकी शुरूआती पढ़ाई बिशप कॉटन बॉय स्कूल में हुई। वहीं इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई सेंट जॉसेफ हाई स्कूल से पूरी की। उसके बाद नंदन नीलेकणि ने अपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से पूरी की। खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के दम पर आईआईटी बॉम्बे में दाखिला पाया था।

नारायण मूर्ति के साथ मिलकर

की इंफोसिस की शुरूआत साल 1978 में उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से होती है। इन दोनों की मुलाकात के बाद ही इंफोसिस की शुरूआत हुई। ये 80 का दशक था। उस दौरान आज के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप काफी अलग था। इस दौर में किसी स्टार्टअप का ग्रो करना काफी मुश्किल काम था। करीब 10 वर्षों तक इंफोसिस काफी मुश्किल हालातों में चलती रही। वहीं साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए मेजर रिफॉर्म ने मानों इंफोसिस को एक नया रास्ता दे दिया हो।

आम लोगों के हित के लिए काम करें आयकर अधिकारी: निर्मला सीतारमण

मुंबई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आयकर अधिकारियों से कहा कि वे आम जनता को

दफ्तरों के चक्कर न कटवाएं और बिना अनावश्यक देरी के उन्हें समय पर और संवेदनशील सेवाएं प्रदान करें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने

मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित 13 मंजिला आयकर सिंधु भवन के उद्घाटन अवसर पर आयकर विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते

हुए यह बात कही। उन्होंने अधिकारियों से आम नागरिकों के हित में कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि लोगों को अपने वैध

कार्यों के लिए दर-दर भटकने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। सीतारमण ने अधिकारियों से नियमों के दायरे में रहते हुए जनता के

कार्यों का समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से निपटारा करने का आग्रह किया। सीतारमण ने कहा कि इस भवन के निर्माण के

लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने में स्वयं आयकर विभाग के अधिकारियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभाग के

अधिकारी ऐसी कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं तो उन्हें आम नागरिकों की समस्याओं का भी बेहतर ढंग से एहसास होना चाहिए।

Reg. No.: 0917500106

सत्यम् शिवम् हास्पिटल

टिकरी, कौड़िहार, प्रयागराज

संचालित सत्यम् पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी 9/9/1A लुकरगंज प्रयागराज के द्वारा

नोट :- हमारे यहाँ हर समय विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं और सभी प्रकार का इलाज कुशलता से किया जाता है।

- 150 बेड की व्यवस्था
- आई0 सी0 यू0
- एन0 आई0 सी0यू0
- आपरेशन थियेटर
- वेन्टीलेटर, वाई0 पैप
- ओ0पी0डी0
- ई0 सी0 जी0
- डिजिटल एक्स-रे
- पैथोलॉजी
- अल्ट्रासाउण्ड
- नार्मल डिलीवरी
- आपरेशन से डिलीवरी की व्यवस्था
- 24 घंटा ऑक्सीजन की सुविधा
- 24 घंटा इमरजेन्सी की सुविधा
- एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध

निर्देशक : संजय शुक्ल

सम्पर्क सूत्र : 9451181332, 9198860735

कालेज कोड 01083

सत्यम् शिवम् शुभम् ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स

टिकरी, धरवनपुर, प्रयागराज

सम्बद्ध प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।

हेल्पलाइन नं.: 9451181332, 9198860735

Website : <http://sssgroup.co.in>

SATYAM SHIVAM SHUBHAM GROUP OF INTITION

TIKRI PRAYAGRAJ

Course

B.A., M.A., B.Sc, M.Sc., (Ag)
B.Com., M.Com., LL.B.
B.A.LL.B., B.Pharm
D.Pharm, ITI, BTC.

संजय शुक्ल
चेयरमैन

राजकुमारी शुक्ला
निर्देशक

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोरांव में किया कार्यकताओं से संवाद

मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाभी

सबसे तेज प्रयागराज सोरांव। सपा फर्जी पीडीए की बात करती है ये सत्ता में आने के लिए बेकारा है पर 2027 हर हाल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी डबल इंजन की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य किया है सोरांव मेरी कर्म भूमि है मै आऊं तो बीच में हूं न आऊँ तो भी आपके बीच में हूं 2014 के लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा में 50000 से अधिक वोटो से मुझे यहां की जनता ने सांसद बनाया 2017 से पहले पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर थी युवाओं महिलाओं किसानों की तमाम

कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता था 2017 मे सोरांव फाफामऊ फुलपुर तो जीते पर हंडिया और प्रतापपुर हार गए 2027 पांचों विधानसभा जीतना है। सोरांव विधानसभा अभी अपना दल के पास है पर इसको भी भाजपा के कोटे में लाने के लिए मै चर्चा कर रहा हूं सोरांव से प्रतापगढ़ जाने पहले 2 घंटा लगता था पर आज 40 मिनट में हम वहां पहुंच रहे हैं सड़को का जाल बिछाया जा रहा है हर घर तक सड़क बनाई जाएगी बिना किसी भेदभाव के घर घर जल पहुंचाया जा रहा है कोई जाति



धर्म का हो भाजपा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है पिछली सरकार में 8 घंटे बिजली मिलती थी पर आज 18 घंटे बिजली मिल

रही हैं सपा सरकार में जो पैसा विकास के लिए आता था उसी सैफई महोत्सव में लगा दिया जाता था। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब

देगी यह बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोरांव में कार्यकताओं के संवाद करते हुए कही इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्या, जिलाध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान, एमएलसी सुरेन्द्र चौधरी,विधायक गुरु प्रसाद मौर्या, पूर्व विधायक प्रभा शंकर पांडेय पूर्व जिलाध्यक्ष कविता पटेल कन्हैया लाल पांडेय, जिला मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष संजीव द्विवेदी, सुशील महाराज,संचालन जिला महामंत्री मनोज निषाद ने किया तथा पुरुषोत्तमपुर और गारापुर में गौतम बुद्ध,डॉ भीम राव

अम्बेडकर, महाराणा प्रताप सिंह, संत गाडगे आदि महान विभूतियों की प्रतिमा का लोकार्पण किया तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सभी सौंपी इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक फूलपुर दीपक पटेल जिलाध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान, ब्लॉक प्रमुख डब्बू यादव, पार्षद अरुण कुमार मिश्रा,एसीपी थरवाई अरुण पराशर, विनय तिवारी, अनिल पटेल सहित थानाध्यक्ष थरवाई संतोष पांडेय आदि मौजूद रहे। तथा सहसौ ब्लॉक के नव सृजित भवन का लोकार्पण भी किया।

कारगिल विजय दिवस पर अमर शहीद लांस नायक विजय शुक्ल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

सबसे तेज प्रयागराज प्रतापगढ़। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विकासखंड कुंडा क्षेत्र के बेधन गोपालपुर गांव में अमर शहीद लांस नायक विजय शुक्ल की 27वीं पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। श्रद्धांजलि सम में यातायात निरीक्षक पवन कुमार पाण्डेय ने शहीद विजय शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि



कारगिल विजय दिवस भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत

रहेंगे। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान धर्मराज पटेल, चौकी प्रभारी अवधेश सिंह, श्यामलाल बहेरी, राज कपूर बहरी, संजय बहेरी, संदीप बहेरी, कप्तान बहेरी सहित समस्त बहेरी

15 अगस्त को लालगोपालगंज चौराहे पर होगा ध्वजारोहण

व्यापार मंडल की बैठक में लिया गया निर्णय

सबसे तेज प्रयागराज लालगोपालगंज, प्रयागराज। लालगोपालगंज व्यापार मंडल की बैठक सोमवार को व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालगोपालगंज चौराहे पर भव्य ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के व्यापारी, गणमान्य नागरिक एवं समाजसेवी बड़ी संख्या में



शामिल होंगे। बैठक में फाफामऊ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक गुरु प्रसाद मौर्य के प्रति आभार व्यक्त किया गया। व्यापारियों ने कहा कि विधायक के प्रयासों से जेतवारा रोड स्थित रेलवे फाटक पर आए दिन लगने वाले

जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे क्षेत्रवासियों और व्यापारियों को भविष्य में यातायात जाम से राहत मिलेगी।

बैठक में क्षेत्र के विकास, व्यापारिक हितों एवं आगामी कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों ने नगर के विकास कार्यों में सहयोग का संकल्प लेते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। बैठक में राकेश कुमार केसरवानी (पूर्व सभासद), सीताराम कौशल, जौवार अहमद, मुजाहिद फारुकी, अब्दुल वासे अंसारी, मंसूर अहमद, मुमताज अहमद सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

बमरौली बमबाजी के चार नामजद अब भी फरार २9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, तीन आरोपी जा चुके हैं जेल

सबसे तेज प्रयागराज प्रयागराज। पुरामुफ्ती के बमरौली गांव में प्रांपर्टी डीलर की थार पर बमबाजी और फायरिंग के सनसनीखेज मामले में २१ दिन बाद भी चार नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। फरार आरोपियों में अतीक अहमद के शूटर आबिद प्रधान का दामाद है शमशुल्लेन के रिश्तेदार भी शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार दहशत में हैं और उसने अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस के अनुसार मामले में नामजद शोएब, अबू तलहा, दानिश और शमशुल्लेन अब भी फरार हैं। वहीं, ७

जुलाई को सलीम तथा ८ जुलाई को एहतेशाम और अबू उज्जाफा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तीनों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आया है कि फरार दानिश, अतीक के शूटर आबिद प्रधान का दामाद है शमशुल्लेन के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। उधर, आरोपी अबू तलहा ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक

आरोपियों पर बीते पांच महीनों में तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। २६ फरवरी को नमाज पढ़कर लौट रहे दो सगे भाइयों पर हमले और ३० मई को झपिया गांव में एक युवक पर हमले के आरोप में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि ५ जुलाई की शाम करीब साढ़े छह बजे बमरौली गांव में हमलावरों ने प्रांपर्टी डीलर मशरूर की थार गाड़ी को निशाना बनाते हुए बम फोड़े और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसका वीडियो

भी वायरल हुआ था। पीड़ित मशरूर का आरोप है कि हमलावरों ने राइफल, तमंचों और बमों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला किया। हालांकि गिरफ्तार आरोपी सलीम ने पृछताछ में तमंचे से फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। पुरामुफ्ती थाना प्रभारी अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि चारों फरार नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। एक आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

डेन्जर जोन-2225 गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, चोरी की दो बाइक व 900 रुपये बरामद

सबसे तेज प्रयागराज प्रयागराज। हण्डिया थाना पुलिस ने चोरी और छिनेती की घटनाओं में सक्रिय "डेन्जर जोन-2225" गैंग के दो वांछित सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी व छिनेती की दो मोटरसाइकिल तथा छिनेती के मोबाइल को बेचने से प्राप्त 900 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस आयुक्त एवं अपर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत डीसीपी गंगानगर, एडीसीपी गंगानगर तथा एसीपी हण्डिया के नेतृत्व में हण्डिया पुलिस ने शनिवार को भीटी ओवरब्रिज के पास से सूरज

गौतम (20) निवासी किरांव तथा आकाश गौतम (21) निवासी होलापुर, थाना हण्डिया को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से थाना हण्डिया में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे से संबंधित एक बजाज प्लेटिना बाइक बरामद हुई। पृछताछ और आरोपितों की निशानदेही पर थाना सुरियावां (भदोही) क्षेत्र से चोरी की गई एक हारो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इसके अलावा थाना सरायममरेज क्षेत्र में हुई मोबाइल छिनेती के मामले में मोबाइल बेचने से मिले 900 रुपये भी बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर हण्डिया थाने



में दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) की बख़्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार,

22 जुलाई को ग्राम भीटी रमनपुर निवासी एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान

पेड़ से लटका मिला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा

20 वर्षों से रिश्तेदार के साथ रह रहा था मृतक

संजीव विश्वकर्मा

सबसे तेज प्रयागराज

बिजनौर। स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव नौगरा में रविवार सुबह आम के पेड़ से 49 वर्षीय मूकबधिर व्यक्ति का शव लटका हुआ है। सूचना मिलते ही पुर्बेद मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

मृतक की पहचान लोकेश (49) पुत्र होशियार सिंह निवासी गांव नांगलजट, थाना हल्दौर के रूप में हुई। बताया गया कि लोकेश मूकबधिर था और उसके परिवार में कोई सदस्य जीवित नहीं बचा था। इसी कारण वह पिछले करीब 20 वर्षों से अपने रिश्तेदार पुर्बेद के घर रह रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फ़िलहाल मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

फूलपुर में सिपाही का शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम

फतेहपुर में तैनाती के दौरान सीएम के कार्यक्रम में जाते समय दुर्घटना में हुई मौत

मौजी लाल रावत

सबसे तेज प्रयागराज

फूलपुर। फूलपुर थाना क्षेत्र के सराय शेकपीर उर्फ सलमापुर दीवानगंज गांव निवासी रामप्रवेश उम्र 45 वर्ष पुत्र गिरधारी लाल इन दिनों फतेहपुर जनपद के धाता थाना में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। बताया जाता है की। शनिवार को सुबह लगभग 8 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में ड्यूटी करने मोटर साइकिल से जा रहे थे। की रास्ते में एक डम्फर वाहन से जोर दार टक्कर मार दिया। जिससे मौके पर ही उक्त सिपाही की मौत हो गई।

घटना को देखते हुए आस पास के लोगो की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना सभांश्चित थाने में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। विभागी अधिकारियों द्वारा घटना की जानकारी घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोसमार्डम के लिए भेज दिया। परिजन भी घटना की सूचना पाते ही फतेहपुर पोसमार्डम हाउस पहुंच गए। शव के पोसमार्डन के बाद देर रात सरकारी वाहन से शव फूलपुर थाना के सराय शेकपीर उर्फ सलमापुर दीवानगंज पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। आस पास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पवी

अनारा देवी,पुत्री शिल्पा, शिवानी , शालिनी, वा पुत्र अरनव दस वर्ष सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रविवार सुबह उक्त मृतक सिपाही का अंतिम संस्कार छतनाग घाट पे पुलिस फोर्स के बीच सलामी देकर किया गया।

सीआरपीएफ के दरोगा का तालाब में मिला शव, चेहरे पर चोट के निशान ; हत्या की आशंका

सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। सराय ड़नायत थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में रविवार सुबह सीआरपीएफ के एक दरोगा का शव घर के पास स्थित तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोटवा गांव निवासी चंदन सिंह उर्फ बिंदू (46), पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गुप्त सेंटर पण्डिता, फाफामऊ में थी। वह शुक्रवार को अपनी मां का इलाज कराने के लिए अवकाश लेकर घर आए थे। परिजनों के अनुसार शनिवार शाम चंदन गांव के चौराहे पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका। रविवार सुबह घर के पास स्थित महुआ सागर तालाब में उनका शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। उनकी स्कूटी तालाब के दूसरे किनारे सड़क पर खड़ी मिली। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

घटना की जानकारी मिलने पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमांड अधिकारी अमित सक्सेना भी जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।



सरल स्वभाव की रही चर्चा

फूलपुर। फूलपुर थाना अंतर्गत सराय शेकपीर उर्फ सलमापुर दीवानगंज निवासी मृतक सिपाही रामप्रवेश 45 वर्ष का सरल स्वभाव वा लोगो के बीच का अपना पन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। हजारों लोगों के जुवान से एक ही शब्द निकलता है की। सिपाही के पद पर तैनात होते हुए भी सरल स्वभाव होने के नाते सभी से मिलनसार का स्वभाव आपसी चर्चा का विषय बना हुआ है। घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति दुनिया छोड़ कर चला गया। बड़ी पुत्री शिल्पा की शादी के बाद अभी दो पुत्री एवं एक पुत्र

को शादी बाकी है।



सबसे तेज प्रयागराज प्रयागराज। सराय ड़नायत थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में रविवार सुबह सीआरपीएफ के एक दरोगा का शव घर के पास स्थित तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

1/3

संपादकीय

कर-संस्कृति: विकसित भारत का अदृश्य संविधान

राष्ट्र की शक्ति केवल मतगणना से नहीं, करगणना से भी मापी जाती है। मतपत्र नागरिक की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है, तो आयकर रिटर्न उसकी आर्थिक निष्ठा का। विडंबना यह है कि मतदान पर व्यापक विमर्श होता है, पर कर-अनुशासन पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती। जबकि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की स्थिरता का वास्तविक आधार उसकी कर-संस्कृति होती है। 24 जुलाई का आयकर दिवस इसी मौन सत्य का स्मरण कराता है कि राष्ट्र का भविष्य केवल बजट नहीं, बल्कि करोड़ों ईमानदार करदाताओं के निष्ठापूर्ण योगदान से आकार लेता है। विकसित भारत का आधार केवल नीतियों नहीं, बल्कि उत्तरदायी कर-संस्कृति है। इसलिए आयकर दिवस किसी विभागीय औपचारिकता का नहीं, आर्थिक नागरिकता के सम्मान का अवसर है। इतिहास गवाह है कि समृद्ध राष्ट्रों की नींव केवल संसाधनों पर नहीं, सुदृढ़ कर-संस्कृति पर टिकी होती है। भारत में आधुनिक आयकर व्यवस्था का औपचारिक आरंभ 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा स्तुतुत आयकर अधिनियम से हुआ, किंतु स्वतंत्र भारत ने इसे केवल राजस्व-संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बनाया। 1961 के आयकर अधिनियम के बाद सरलीकरण की दिशा में नया आयकर कानून भी प्रस्तावित/लागू होने की प्रक्रिया में है, प्रत्यक्ष कर प्रशासन में सुधार, कंप्यूटीकरण, केंद्रीकृत प्रसंस्करण और डिजिटल कर प्रणाली उसी दृष्टि के क्रमिक विस्तार हैं। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है और वैश्विक संस्थाएँ उसे आने वाले दशक का विकास-प्रेरक मान रही हैं। इस उपलब्धि के मूल में करोड़ों ईमानदार करदाताओं से निर्मित वही राजस्व है, जिसने विकास की गति को निरंतर बनाए रखा।

हर सार्वजनिक उपलब्धि के पीछे एक मौन निवेश छिपा होता है—करदाता का। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित संस्थानों, रक्षा आधुनिकीकरण, डिजिटल अवसंरचना, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वास्तविक नींव ईमानदारी से अदा किए गए कर पर टिकी है। नागरिक अपनी आय का एक अंश राष्ट्र को देकर केवल राजस्व नहीं देता, बल्कि समान अवसरों वाले भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। इसलिए विकसित देशों में कर भुगतान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहाँ करदाता राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का सह-शिल्पी माना जाता है।

कर प्रशासन का नया चेहरा कानूनों से कम, तकनीक से अधिक गढ़ा गया है। कभी आयकर कार्यालयों के चक्कर, कागजी फाइलें और लंबी प्रतीक्षाएँ करदाताओं की विवशता थीं; आज फेसलेस असैसमेंट, प्री-फिलड आयकर रिटर्न, ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल भुगतान और कृत्रिम बुद्धिमता आधारित जोखिम विश्लेषण ने प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और विश्वसनीय बना दिया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में निरंतर वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरल व्यवस्था स्वीच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने भी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की प्रगति को उल्लेखनीय माना है। तकनीक का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं, बल्कि करदाता और शासन के बीच भरोसे का स्थायी सेतु बनाना है। इसलिए आज करदाता व्यवस्था से डरता नहीं, उस पर भरोसा करता है। कर भुगतान का सबसे बड़ा लाभ सरकार नहीं, स्वयं करदाता प्राप्त करता है। नियमित आयकर रिटर्न आय, व्यय, निवेश और बचत का अनुशासित लेखा विकसित करता है, जो बैंकिंग, ऋण, उद्यमिता और वित्तीय सुरक्षा की मजबूत आधारशिला बनता है। जनधन, डिजिटल भुगतान, यूपीआर और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने नागरिक को अधिक वित्तीय रूप से जागरूक बनाया है। आज करदाता केवल कर अदा करने वाला नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन का प्रतिनिधि है। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती वित्तीय साक्षरता इसी परिवर्तन का संकेत है। नई पीढ़ी जब कर को दंड नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व मानेगी, तभी आर्थिक राष्ट्रवाद विचार नहीं, व्यवहार बनेगा।

विश्व में भारत के खिलाफ नरैटिव गढ़ता बीबीसी

संजय सक्सेना

दुनिया भर में अपनी पत्रकारिता के कारण सुर्खियों में रहने वाला बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) का विवाद से गहरा नाता रहा है। कई देश बीबीसी की खबरों को सच के द्वाएजेंडेक के रूप में देखते हैं। बीबीसी पर भारतीय राजनीति, समाज और नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए एजेंडा-आधारित पत्रकारिता और नरैटिव मैनिपुलेशन (कहानियों को तोड़ने-मरोड़ने) के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। आलोचकों, विचारकों और भारत सरकार के समर्थकों का मानना ​​है कि बीबीसी अक्सर भारत की नकारात्मक छवि पेश करता है और संवेदनशील मुद्दों पर एकतरफा दृष्टिकोण अपनाकर असंतोष को भड़काता है। ऐसा ही कुछ कॉंक्रेच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भी देखने को मिल रहा है।बीबीसी की रिपोर्टें पर नजर डालने से कुछ विशेष पैटर्न सामने आते हैं, जिनके जरिए खबरों को एक खास दिशा दी जाती है। भारत से जुड़ी खबरों में ऐसे शीर्षकों का चयन किया जाता है, जो सीधे तौर पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सरलीकृत करके सीधे तौर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में पेश किया जाना। बीबीसी का लोकल नरैटिव को ग्लोबल एजेंडा बनाना भी अक्सर चिंताजनक नजर आता है। उसके द्वारा स्थायी स्तर के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय राजनीति और सरकार की नीतियों से जोड़कर दिखाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। बीबीसी द्वारा अपनी रिपोर्ट में केवल उन्हीं विचारकों, पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता है, जो सरकार विरोधी रुख रखते हैं। बीबीसी की दखलअंदाजी और मैनिपुलेशन के कई उदाहरण मौजूद हैं।बीबीसी द्वारा 2023 में दो भागों में जारी की गई इंडिया: द मोदी क्वेश्चनह डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को ऐसे समय पर रिलीज किया गया, जब भारत जी-20 (जी-20) की अध्यक्षता संभाल रहा था और वैश्विक मंच पर अपनी छवि मजबूत कर रहा था। इसमें भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित एसआईटी की उस जांच को पूरी तरह नजरअंजक कर दिया गया, जिसने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। दरअसल, बीबीसी का उद्देश्य कानूनी रूप से सुलझ चुके इस संवेदनशील और ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे को दोबारा हवा देकर देश में राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष पैदा करना था। साल 2020-2021 में भारत सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हुए विप्रदर्शन के दौरान बीबीसी की कवरेज को बेहद एकतरफा माना गया। बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्टर्स और डिजिटल ऑटोकल्स में मुख्य रूप से आंदोलनकारियों के पक्ष को ही सही ठहराया गया।

इसमें लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों को या तो बहुत कम दिखाया गया या उन्हें जायज ठहराने की कोशिश की गई। कानूनों के समर्थन में खड़े करोड़ों छोटे किसानों के दृष्टिकोण को बीबीसी ने अपनी मुख्यधारा की कहानियों में कोई जगह नहीं दी। इस कवरेज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया कि भारत सरकार किसानों का दमन कर रही है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक साख को चोट पहुंची।2020 में समान नागरिक संहिता यानी सीएयू विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान बीबीसी की भूमिका पर गंभीर प्रतिक्रिया उठी। बीबीसी ने सीएए को एक मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में प्रचारित किया, जबकि यह कानून केवल पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए था, न कि किसी भी नागरिकता छीनने के लिए। दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग में बीबीसी ने हिंसा को एकतरफा मुस्लिम विरोधी दंगे के रूप में पेश किया, जबकि दंगों में दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) के लोग मारे गए थे और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा व पुलिस हेड कांस्टेबल रतन लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

अब आगे क्या? इस्तीफा या पेपर लीक पर संसद में बहस?

सौरभ वर्ष्ण्य

देश की संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा, जवाबदेही और समाधान की अपेक्षा की जाती है। लेकिन मानसून सत्र के शुरूआती तीन दिन जिस प्रकार लगातार हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़े हैं, उसने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या संसद जनहित के मुद्दों के समाधान का मंच बनेगी या केवल राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बनकर रह जाएगी? वर्तमान गतिरोध का सबसे बड़ा कारण देश पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक की घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने

लाखों छात्रों के भविष्य, उनकी वर्षों की मेहनत और पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का विषय मानते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री का इस्तीफा केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी तय होने और नैतिक

उत्तरदायित्व के आधार पर होना चाहिए। वहीं विपक्ष का यह तर्क भी पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता कि जब सरकार उपलब्धियों का श्रेय स्वयं लेती है, तो गंभीर प्रशासनिक विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी भी उसे स्वीकार करनी चाहिए। यही कारण है कि इस्तीफे की मांग राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है।

दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि संसद में इस पूरे प्रकरण पर गंभीर, तथ्यात्मक और व्यापक चर्चा हो। केवल नारेबाजी या सदन को बांधित करने से न तो छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और न ही परीक्षा प्रणाली में सुधार

पीएम हाउस पर राहुल का धरना

विवाद, कोई नहीं आया साथ

अजय कुमार

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 21-22 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के निकट किया गया धरना-प्रदर्शन राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ गया है। नीट पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में मल्लिकार्जुन खरेगे, प्रियंका गांधी वाड़ा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया, जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके आवास के बाहर धरना दे रहे थे। कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए वीडियो जारी कर अपने फैसले का बचाव किया। सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी के इस विवादित धरने का कांग्रेस को छोड़कर कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता समर्थन नहीं दे रहा है।गौरतलब है कि यह पूरा घटनाक्रम बड़े और पहले से चल रहे आंदोलन के बीच हुआ। शिक्षा सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर छात्रों के नेतृत्व में चल रहे कॉंक्रेच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहले से जारी थे, और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसी मुद्दे पर लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे थे। वांगचुक की तीन सप्ताह लंबी भूख हड़ताल आंदोलन का प्रतीक बन चुकी थी, और सप्ताहांत में पुलिस द्वारा उन्हें जबरन अस्पताल ले जाए जाने के बाद आंदोलन ने और जोर पकड़ा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित पुलिसिया सख्तों के वीडियो वायरल हुए, जिससे जनाक्रोश और



बढ़ गया।

दिलचस्प बात यह रही कि छात्रों के आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन से एक निश्चित दूरी बनाए रखने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपना अलग धरना शुरू कर दिया, जबकि सीजेपी का प्रदर्शन उससे कुछ किलोमीटर दूर जंतर-मंतर पर चल रहा था। इसी बिंदु पर कई विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि जब मकसद एक ही था, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा, तो कांग्रेस और सीजेपी ने साझा मंच से प्रदर्शन क्यों नहीं किया और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास को ही निशाना बनाया।भाजपा ने इस पूरे प्रकरण को सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के रूप में पेश किया। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सवाल उठाया कि जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति पहले से थी, तो राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास तक क्यों ले गए, और उन्होंने इसे प्रदर्शन भड़काने की कोशिश करार दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी के रवैये को अफसोसजनक बताते हुए कहा कि सरकार बातचीत और संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष के नेता अपनी बात से मुकर गए।

इसके जवाब में भाजपा ने देशभर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर सुरक्षा उल्लंघन

के आरोप में विरोध जताया, जबकि कांग्रेस विधायकों ने कई राज्यों की विधानसभाओं के बाहर भी समर्थन में प्रदर्शन किए।
अब बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या आजादी के बाद देश में इससे पहले भी किसी नेता या राजनीतिक दल ने सीधे प्रधानमंत्री के आवास या कार्यालय के ठीक बाहर इस तरह का धरना-प्रदर्शन किया है। भारत में विरोध-प्रदर्शन की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन इसका केंद्र लगभग हमेशा जंतर-मंतर, रामलीला मैदान, बोट क्लब (अब विजय चौक), इंडिया गेट या संसद भवन परिसर रहा है, न कि सीधे प्रधानमंत्री का निजी आवास। इसकी बड़ी वजह सुरक्षा है। प्रधानमंत्री आवास अत्यंत संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, जहां आमतौर पर धारा 144 जैसी पाबंदियां लागू रहती हैं और सामूहिक जमावड़े या जंतर-मंतर को ही अपना केंद्र बनाया, प्रधानमंत्री आवास को नहीं। यहाँ तक कि इमरजेंसी के बाद के दौर में विपक्ष के तीखे प्रदर्शनों भी संसद परिसर या बोट क्लब तक ही

लोकतंत्र, आंदोलन और जवाबदेही



को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, बल प्रयोग तथा विभिन्न दावों और प्रतिदावों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो और सूचनाएं तेजी से प्रसारित हुईं, जिनमें से कुछ दावों पर बाद में विवाद भी सामने आए। लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का उद्देश्य सरकार और समाज का ध्यान किसी वास्तविक समस्या की ओर आकर्षित करना होना चाहिए। यदि आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटककर हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान, घृणा फैलाने वाली भाषा या कानून हाथ में लेने का माध्यम बन जाए तो उसकी नैतिक वैधता कमजोर पड़ जाती है। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी उसका नैतिक आधार होता है। जब

आएगा। देश यह जानना चाहता है कि आखिर बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था में चुक कहां है? कौन-से संगठित गिरोह इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं? अब तक कितनों पर कार्रवाई हुई? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ठोस रणनीति क्या है? संसद में यदि इन सभी प्रश्नों पर विस्तृत बहस होती है तो यह लोकतंत्र और छात्रों-दोनों के हित में होगा। बहस से जवाबदेही भी तय होगी और सुधार की दिशा भी स्पष्ट होगी। लेकिन यदि बहस से पहले केवल इस्तीफे की मांग और सरकार की ओर से केवल राजनीतिक प्रतिरोध चलता रहा,

तो सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों युवाओं का होगा, जिनका भविष्य इस पूरे विवाद के बीच अधर में लटका हुआ है।

इस बीच राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार व्यापक होता दिखाई दे रहा है। विभिन्न राज्यों से छात्र वहां पहुंच रहे हैं और निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। कुछ समय पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद यह माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शनों की धार कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन

वर्तमान छात्र आंदोलन यह संकेत देता है कि युवाओं का आक्रोश केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के प्रति गहराते अविश्वास का प्रतीक बन चुका है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह पेपर लीक पर संसद में चर्चा करने और आंदोलनरत छात्रों से संवाद के लिए भी तैयार है। यदि ऐसा है, तो यह स्वागतयोग्य पहल हो सकती है। लोकतंत्र में संवाद ही किसी भी संकट का सबसे प्रभावी समाधान माना जाता है। लेकिन संवाद तभी सार्थक होगा जब उसके साथ ठोस निर्णय, समयबद्ध कार्रवाई और पारदर्शिता भी जुड़ी हो।

सिक्किम हादसा: प्रकृति की चेतावनी या मानवीय लापरवाही ?

सुनील कुमार महाला

हाल ही में सिक्किम के समरडुंग, नामची जिले में एनएचपीसी की तोस्ता स्ट्रेज-श्क जलविद्युत परियोजना के निमाणांधीन टनल (एडीआईटी-3) में हादसा हो गया। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2026 को निमाणांधीन सुरंग के अंदर अचानक मीथेन गैस से जुड़ी घटना (संभावित विस्फोट/दहन) हुई और इसके बाद सुरंग के प्रवेश मार्ग के पास भूस्खलन हुआ, जिससे सुरंग का हिस्सा बंद हो गया और अंदर मौजूद कर्मचारी व अधिकारी फंस गए। बताया जा रहा है कि सुरंग में 40 से अधिक लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन लगभग 25इप्ट लोग अंदर फंस गए। जानकारी अनुसार इनमें एनएचपीसी, टेकेदर कंपनी और मजदूर शामिल थे।

ताजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार(यह आलेख लिखे जाने तक) 20 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं तथा 2 लोग सुरक्षित बाहर निकले हैं में सफल रहे तथा रिपोर्ट के समय तक 5 लोगों की तलाश जारी थी। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि सुरंग में प्राकृतिक रूप से जमा मीथेन गैस को निकालने के प्रयास के दौरान विस्फोट/दहन हुआ, जिससे भूस्खलन हुआ और सुरंग का प्रवेश मार्ग बंद हो गया। हालाँकि, अंतिम कारण विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। राहत एंव बचाव कार्य में राज्य पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, दमकल तथा अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों को लगाया गया। इधर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की है। बहरहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि भूस्खलन के कारण इस सुरंग के ढह जाने से कई लोगों की मौत हो जाने की घटना ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ों की पारिस्थितिकी की अनदेखी कर विकास कितना नुकसानदेह हो सकता है, यह अब कोई छिपी बात नहीं है।

हाल फिलहाल, यहां पाठकों को बताता चलूँ कि हमारे देश में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) एक गंभीर प्राकृतिक आपदा बताा जा रहा है। मानसून के दौरान हिमालयी और पश्चिमी घाट के राज्यों में इसकी घटनाएं लगावार बढ़ रही हैं। हाल के दिनों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण कई बड़े भूस्खलन हुए हैं। वास्तव में, अत्यधिक वर्षा और बादल फटना, भारत के हिमालयी क्षेत्र का भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होना, अनियोजित विकास (पेड़ों की अंधाधुंध कटाई,सड़क, सुरंग, जलविद्युत परियोजनाओं और भवन निर्माण के दौरान वैज्ञानिक मानकों की अनदेखी), विकास के नाम पर पहाड़ों का काटा जाना, जलवायु परिवर्तन (अत्यधिक और अल्प अवधि की वर्षा) भूस्खलन के प्रमुख कारणों में से एक हैं। तथा जम्मू-कश्मीर,लद्दाख,हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड,सिक्किम,अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,मेघालय,दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) तथा पश्चिमी घाट (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र) हमारे देश में सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। गौरतलब है कि भारत का लगभग 12.6% भौगोलिक क्षेत्र भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र में आता है तथा इस क्रम में इसरो (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र) ने वर्ष 1998इप्ट2022 के दौरान भारत में लगभग 80,000 भूस्खलनों का डेटाबेस तैयार किया है। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूँ कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।बहरहाल, भूस्खलन का यह हमारे देश में पहला हादसा नहीं है। उत्तराखंड और तेलंगाना में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन उनसे कोई सबक नहीं लिया गया। कहना गलत नहीं होगा कि हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में यदि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, तो यह गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि बरसात के मौसम में सुरंग निंटाजान का काम करने समय आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए?

सार्वजनिक संपत्ति का महत्व भी इसी संदर्भ में समझना चाहिए। सड़कें, बसें, रेलवे, सरकारी विद्यालय, अस्पताल, पुल और अन्य सार्वजनिक संस्थान किसी सरकार या राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होते। इनका निर्माण जनता के करों से होता है। इसलिए विरोध प्रदर्शन के दौरान यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका वास्तविक नुकसान देश के नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। मरम्मत और पुनर्निर्माण का खर्च भी अंततः करदाताओं के धन से पूरा होता है। इसलिए लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला दायित्व सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा होना चाहिए।

पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका भी लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायालयों तथा संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना है। यदि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला होता है, पथराव किया जाता है या सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई जाती है तो वह भी कानून के विरुद्ध है। दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई भी आवश्यक, अनुपातिक और विधिसम्मत होनी चाहिए। लोकतंत्र में न तो भीड़ को हिंसा का अधिकार है और न ही राज्य को अनावश्यक बल प्रयोग का। यही संतुलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखता है। लोकतंत्र में जवाबदेही केवल सरकार की नहीं होती, बल्कि नागरिकों और आंदोलनों की भी होती है। यदि किसी आंदोलन में कुछ लोग हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पूरे आंदोलन या पूरे समाज को एक ही दृष्टि से देखना न्यायसंगत नहीं होगा। इसी प्रकार यदि किसी सरकारी एजेंसी से भी कानून या मानवाधिकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही भी आवश्यक है। यही कानून के शासन की मूल भावना है। भारतीय संविधान केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। अनुच्छेद 51ए प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है कि वह संविधान का सम्मान करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करना है। यदि नागरिक केवल अधिकारों की मांग करें और कर्तव्यों की उपेक्षा करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी।

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ सारनाथ, उत्तर प्रदेश को मिला चौथा विश्व धरोहर स्थल

वाराणसी। लगभग 28 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान बुद्ध की प्रथम धर्मदेशना स्थली सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में शनिवार शाम इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की गई। इसके साथ ही सारनाथ भारत का 45वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इस उपलब्धि से बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में शामिल सारनाथ को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है।

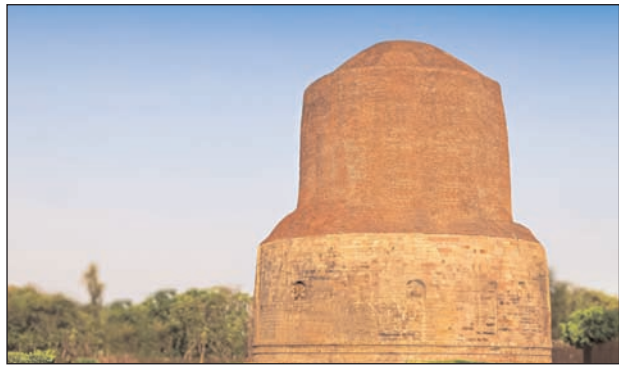
साथ ही, उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के मानचित्र पर नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सारनाथ को 3 जुलाई 1998 को यूनेस्को की टेरेटिव (संभावित) सूची में शामिल किया गया था।



लगभग 28 वर्षों बाद मिली यह मान्यता उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्व रखती है। अब तक राज्य के तीन विश्व धरोहर स्थल—ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी—आगरा मंडल तक सीमित थे। सारनाथ के शामिल होने से प्रदेश की विश्व धरोहर पहचान पूर्वांचल तक विस्तृत हो गई है और राज्य की समृद्ध बौद्ध विरासत को वैश्विक मान्यता मिली है।

—चौखंडी स्तूप और पुरातात्विक

अवशेषों को मिली मान्यता
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्व धरोहर संपत्ति में चौखंडी स्तूप तथा सारनाथ का पुरातात्विक परिसर शामिल है। दोनों स्थल एक-दूसरे से लगभग 626 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध और उनके पांच प्रथम शिष्यों के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जबकि पुरातात्विक परिसर में धामेक स्तूप, धर्मराजा स्तूप, प्राचीन विहारों के अवशेष और अशोक स्तंभ जैसे



महत्वपूर्ण स्मारक शामिल हैं। ये स्मारक सारनाथ के विश्व के प्रमुख बौद्ध आस्था एवं ज्ञान केंद्र के रूप में हुए ऐतिहासिक विकास की गवाही देते हैं। —**बौद्ध धर्म में सारनाथ का विशेष महत्व**
सारनाथ वही पावन स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश देकर 'धर्मचक्र प्रवर्तन' की शुरुआत की थी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख 'ऋषिपत्तन' के नाम से मिलता है।

यहीं भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम पांच शिष्यों को धर्म का उपदेश देकर करुणा, शांति और मध्यम मार्ग का संदेश मानवता को दिया था। करीब 2600 वर्षों से सारनाथ बौद्ध आस्था, तीर्थ परंपरा, मठ जीवन, प्राचीन स्थापत्य और समृद्ध कला विरासत का प्रमुख केंद्र रहा है। यूनेस्को की यह मान्यता इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगी।

कांवड़ यात्रा क्या है, क्या है इसका महत्व, श्रीराम और रावण भी लाए थे कांवड़

लखनऊ। कांवड़ यात्रा भारत की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है। इस साल 30 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होगी। इसी दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। कांवड़ यात्रा में शिवभक्त अपनी अपनी श्रद्धानुसार कांवड़ उठाते हैं। यह बाते काशी के विद्वान एवं ज्योतिषाचार्य प्रसाद दीक्षित ने हिन्दुस्थान समाचार से एक विशेष बातचीत में बताया। उन्होंने बताया कि सावन में जो भी शिवभक्त कांवड़ यात्रा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गौरतलब है इस साल कांवड़ मेला 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त (सावन शिवरात्रि) तक चलेगा। **क्या है कांवड़ यात्रा**
उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को सीधे तौर पर भगवान शिव से जोड़ा जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये यात्रा की जाती है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा के



साथ ही सहनशक्ति और सामूहिक एकता की यात्रा है। कांवड़ यात्रा से अंतर्मन शुद्ध होता है। कांवड़ शिव भक्ति की यात्रा है। कांवड़ यात्रा के दौरान मांस मंदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। इस दौरान तामसिक भोजन भी वर्जित होता है। कांवड़ यात्रा शरीर के साथ-साथ मन की भी यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा में 10 दिन बेहद ही अनुशासन से भरे होते हैं। इन्ही दिनों को अपने जीवन में उतारने की सीख भी कांवड़ यात्रा से मिलती है।

राम, रावण और श्रवण ने की

थी कांवड़ यात्रा
उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव शिव के नियमित पूजन के लिए पुरा महर्देव (जनपद बागपत) में मंदिर की स्थापना की। परशुराम ने कावड़ में गंगाजल लाकर पूजन कर कावड़ परंपरा की शुरुआत की। वर्तमान में देशभर में कांवड़ यात्रा काफी प्रचलित है। कथा के अनुसार कावड़ परंपरा शुरू करने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी श्रावण मास में की जानी चाहिए।

बिजनौर में बनेगा शहीद स्तंभ और शौर्य वाटिका, कारगिल विजय दिवस: श्री काशी विश्वनाथ धाम में सेना के शौर्य को युवाओं ने किया नमन

बिजनौर। उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषद बिजनौर द्वारा देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की स्मृति में एक शहीद स्तंभ और 'शौर्य वाटिका' का निर्माण कराया जाएगा। बैराज रोड स्थित इंदिरा पार्क के बाहर इस शहीद स्तंभ के निर्माण के लिए पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, भाजपा नेता डॉ. बीरबल सिंह और मेजर अभिनव सिंह ने रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। भूमि पूजन का संचालन पंडित चेतन शर्मा ने किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष



श्रीमती इंदिरा सिंह ने कहा कि नगर में वीर सैनिकों की याद में इस भव्य शहीद स्थल का निर्माण किया जाना उनके लिए बेहद

गौरव की बात है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद करने का इससे बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो

सकता। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कप्तान अनिल कुमार गुप्ता, सैनिक अरविंद लॉबा, सभासद संजय बिश्नोई, मनोरमा शर्मा, बबिता चौधरी, अमित ठाकुर, हितेश सैनी, आदिल, प्रभाकर, अभिषेक राणा, राजवीर सिंह, कासिम साहू, ब्रह्मपाल सिंह, राम अवतार सिंह, शमशाद अहमद, सुरेंद्र सिंह, वंदना अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, मनोज कुमार मनी और हितेश सैनी , पालिका के अधिशासी अधिकारी (एड) रामपाल सिंह यादव सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

वाराणसी। कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में नमामि गंगे के तत्वावधान में भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर देश की सुरक्षा एवं समृद्धि के साथ वीर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। कार्यक्रम के दौरान बाबा



विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार एवं भारत माता की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित लोगों ने भारतीय सेना के शौर्यवीरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए

दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों और विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

कार्यक्रम में नीरज सिंह, सौरभ पाण्डेय, शशिभूषण पाण्डेय, अर्जुन सिंह, नमन भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ा गया, जहां भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस, अनुशासन और पराक्रम

पढ़ाई में पीछे छूटे बच्चों को मुख्यधारा में लाएगी सरकार, कैच-अप शिक्षण अभियान को मिलेगी गति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी शिक्षा में अधिगम अंतर (लर्निंग गैप) को समाप्त करने के लिए कैच-अप शिक्षण अभियान को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों, बीआरसी, बीएसए कार्यालयों और डायट में कैच-अप शिक्षण, निपुण लक्ष्य, कक्षा शिक्षण की 10 प्रभावी प्रथाओं तथा रीडिंग कैपेन से संबंधित आईईसी सामग्री 31 जुलाई तक प्रदर्शित की जाएगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में सहायक शिक्षा निदेशकों (बैसिक), डायट प्राचार्यों, जिला बैसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों, एसआरजी तथा एआरपी को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं।

निदेशों में कहा गया है कि संबंधित आईईसी सामग्री का मुद्रण कराकर उसे विद्यालयों, बीआरसी, बीएसए कार्यालयों तथा डायट में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए ताकि शिक्षक प्रतिदिन इन शैक्षणिक संदेशों का उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकें। इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में दक्षता आधारित शिक्षण की एक समान कार्यसंस्कृति विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कैच-अप शिक्षण के लिए तैयार की गई 15 सूत्रीय रणनीति अभियान के प्रभावी संचालन के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत अधिगम स्तर से पीछे रह गए बच्चों की पहचान, आधारभूत दक्षताओं का आकलन, स्तरानुसार समूह बनाकर शिक्षण, दैनिक एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना, गतिविधि आधारित शिक्षण, टीएलएम का प्रभावी उपयोग, नियमित अभ्यास, सतत मूल्यांकन, रीडिंग गतिविधियों को बढ़ावा, अभिभावकों की सहभागिता तथा बच्चों की प्रगति की निरंतर निगरानी पर विशेष बल दिया गया है। उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक पहुंचाना और सीखने की कमी को समयबद्ध ढंग से दूर करना है। **'निपुण लक्ष्य' से स्पष्ट होंगे अधिगम मानक**
विद्यालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले 'निपुण लक्ष्य' पोस्टरों में बालवाटिका से लेकर कक्षा 5 तक भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी के स्पष्ट अधिगम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के सामने प्रत्येक कक्षा की अपेक्षित दक्षताएं स्पष्ट रहेंगी तथा शिक्षण और मूल्यांकन को परिणाम आधारित बनाया जा सकेगा। **कक्षा शिक्षण की 10 प्रभावी प्रथाओं को मिलेगा बढ़ावा**
आईईसी सामग्री में कक्षा शिक्षण की 10 प्रभावी प्रथाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें बच्चों की सक्रिय सहभागिता, गतिविधि आधारित शिक्षण, खुले प्रश्नों का प्रयोग, लेखन एवं पठन अभ्यास, टीएलएम का प्रभावी उपयोग, सतत मूल्यांकन, नियमित प्रतिपुष्टि और सहयोगात्मक अधिगम जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया गया है। इन प्रथाओं का उद्देश्य कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी और परिणामोमुख बनाना है।

ससुराल की प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने गला काटा, पुलिस कर रही जांच

कानपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर के नरवल क्षेत्र में ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता ने रविवार को मायके में चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। नरवल निवासी रखसाना की शादी करीब 16 वर्ष पहले बांदा के मर्दन नाका निवासी यासीन से हुई थी। उनकी 11 वर्षीय बेटी है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से पति यासीन, सास जिजरत, ससुर इमाम बख्श और देवर हसीन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत और समझौते की कोशिशें हुईं, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि 10 जनवरी 2025 को मारपीट के बाद रखसाना को ससुराल से निकाल दिया गया था। उसके जेवर, कपड़े और अन्य स्त्रीधन भी ससुराल पक्ष ने अपने पास रख लिया।

प्रयागराज में बढ़ रहा है गंगा-यमुना का जलस्तर

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हो रही बारिश के बीच गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं और सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की जारी रिपोर्ट के अनुसार खतरे का निशान 84.734 मीटर निर्धारित है। यमुना नदी का जलस्तर नैनी में 74.51 मीटर दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे में 32 सेंटीमीटर बढ़ा है।

पत्नी से विवाद के बाद हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, साढ़े पांच घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा ससुराल पक्ष को बुलाने की जिद पर अड़ा रहा, पुलिस व परिजनों की समझाइश के बाद देर रात सुरक्षित उतरा

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अजीतमल क्षेत्र में शनिवार रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवक हाईटेंशन विद्युत लाइन के टावर पर चढ़ गया। करीब साढ़े पांच घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के दौरान युवक ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। पुलिस, परिजनों और ग्रामीणों की लगातार कोशिशों के बाद देर रात उसे सकुशल नीचे उतार लिया गया। घटना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम नवले का पुरवा की है।

गांव निवासी 27 वर्षीय योगेंद्र सिंह पुत्र बुजेंद्र राव शनिवार रात करीब 8:30 बजे अपने खेत में लगे हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही उसके भाई विवेक संसेत परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां एकत्र हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने योगेंद्र को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। उसने साफ कहा कि जब तक उसके ससुराल पक्ष के

लोग मौके पर नहीं आएंगे, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी मौके पर बुला लिया, ताकि किसी भी अग्रिय घटना से निपटा जा सके। सूचना पर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक से लगातार बातचीत करते रहे। पुलिस ने उसकी पत्नी हेमलता के मायके पक्ष को भी सूचना दी। देर रात बकेवर क्षेत्र के लुधियानी गांव निवासी उसके साले

आलोक कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक योगेंद्र को समझाया और शांत कराया। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे युवक सुरक्षित टावर से नीचे उतर आया। बताया गया कि योगेंद्र विवाहित है और उसका एक पुत्र भी है। युवक के सुरक्षित नीचे आने के बाद पुलिस, परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद की बात सामने आई है।

औरैया : अंतिम संस्कार के तीन दिन बाद जिंदा घर लौटा युवक, पुलिस के सामने अब 'असली शव' की गुत्थी



किसका था। पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है। मामला सैदपुर गांव का है।

दरअसल अजीतमल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे पर भीखेपुर बाजार के पूर्व

विधायक मदन सिंह गौतम के जर्जर होटल के खंडहर के पास कई दिन पुराना एक अज्ञात शव मिला था। शव का आधा चेहरा क्षतिग्रस्त होने से उसकी पहचान मुश्किल थी। इसके बावजूद सैदपुर गांव निवासी दशरथ सिंह और गांव के कुछ लोगों ने शव की पहचान भाई कमल सिंह के रूप में कर दी। इसी आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने कमल सिंह की

पत्नी सुनीता को पृछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले खेत को लेकर पति से विवाद हो गया था। गुस्से में उन्होंने कमल सिंह से कहा था कि जब तक 2 लाख रुपये की व्यवस्था न हो जाए, तब तक घर न लौटें। इसके बाद कमल सिंह घर छोड़कर चले गए थे। वह मजदूरी कर तीन बच्चों का पालन-पोषण कर रही थीं और हाल ही में नौकरी की तलाश में नोएडा गई थीं। वहीं उन्हें पति की मौत की सूचना मिली। गांव पहुंचने तक अंतिम संस्कार हो

चुका था। पृछताछ के दौरान सुनीता ने पुराने मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया। एक नंबर पर बात होने के बाद कमल सिंह से संपर्क हो गया। पत्नी से पूरी घटना जानने के बाद कमल सिंह शनिवार देर शाम गांव पहुंच गए। उन्हें जीवित देखकर परिजन और ग्रामीण दंग रह गए। कमल सिंह ने बताया कि वह पहले पानीपत में मुर्गी फार्म पर काम करते रहे, फिर ट्रक डेल्वर बने और बाद में ग्वालियर में प्लंबिंग का काम करने लगे।

पंजाब-चंडीगढ़ में मानसून फिर सक्रिय, 28-29 को भारी बारिश का अंरेंज अलर्ट
शनिवार सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर, कपूरथला में सर्वाधिक 40 मिमी वर्षा
चंडीगढ़ ।

पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मानसून ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार सुबह से जारी बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अंरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शनिवार सुबह से पठानकोट और जालंधर समेत आसपास के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे वातावरण में ठंडक चुली है। बीते 24 घंटों में कपूरथला में सर्वाधिक 40.0 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा पठानकोट में 30.0 मिमी, रूपनगर (भाखड़ा बांध) में 26.5 मिमी और अमृतसर में 20.6 मिमी वर्षा हुई है। बारिश के बावजूद, पिछले 24 घंटों में पंजाब के अधिकतम तापमान में औसत 2.6 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि यह सामान्य के आसपास ही बना हुआ है। फरीदकोट 36.5° डिग्री ल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि पठानकोट में न्यूनतम तापमान 23.6एछ दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 26 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन 27 जुलाई से राज्य में बारिश की रफ्तार फिर बढ़ेगी। 28 और 29 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश की प्रबल संभावना है, जिसके लिए अंरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई को भी अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। आगामी भारी बारिश के मद्देनजर, चंडीगढ़ सहित निचले इलाकों और शहरी क्षेत्रों में जलभराव की गंभीर आशंका जताई गई है। लोगों को खयब मौसम के दौरान सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

बीओआई का मुनाफा 36 फीसदी बढ़कर 3,068 करोड़ हुआ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में एकल आधार पर अपने मुनाफे में 36.23 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जो 3,067.90 करोड़ रुपये रहा। बैंक के इस मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को मुख्य रूप से गैर-ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार से बल मिला। बैंक ऑफ इंडिया ने एकीकृत आधार पर भी 80.51 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज करते हुए 3,302.58 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 1,829 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की गैर-ब्याज आय 19.07 प्रतिशत बढ़कर 2,579 करोड़ रुपये हो गई, जबकि मुख्य शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 12.61 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,833 करोड़ रुपये रही। इस दौरान बैंक की ऋण वृद्धि 18.64 प्रतिशत दर्ज की गई। परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, जहां बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) दर जून 2026 में घटकर 1.81 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 2.92 प्रतिशत थी। वहीं, शुद्ध एनपीए दर भी 0.51 प्रतिशत पर आ गई, जो जून 2025 में 0.75 प्रतिशत थी।

फर्जी %एयर सुविधा 2.0% वेबसाइटों से सावधान रहें यात्री, सरकार ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली, ।
केंद्र सरकार ने शनिवार को यात्रियों से अपील की कि वे %एयर सुविधा 2.0% की आधिकारिक वेबसाइट की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही अपनी व्यक्तिगत या यात्रा संबंधी जानकारी साझा करें, क्योंकि कुछ फर्जी वेबसाइटें लोगों को ठग रहे कर रही हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि कुछ फर्जी वेबसाइटें और पोर्टल एयर सुविधा 2.0 के नाम पर खुद को आधिकारिक बताकर यात्रियों को पेमेंट गेट पर भेज रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा, «यात्रियों को सूचित किया जाता है कि एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह निशुल्क हैं और सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। एयर सुविधा 2.0 का एकमात्र आधिकारिक पोर्टल है।» मंत्रालय ने आगे कहा कि यात्री अपनी व्यक्तिगत या यात्रा संबंधी जानकारी साझा करने से पहले वेबसाइट के यूआएल की अच्छी तरह जांच करें और एयर सुविधा 2.0 सेवा देने का दावा करने वाली किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर भुगतान करने से बचें। मंत्रालय ने कहा, «यात्रियों से अनुरोध है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें और सही जानकारी के लिए केवल सरकार की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 3,030 करोड़ के 3 भत्य केमिकल पार्कों को दी मंजूरी

भय-रसायन योजना के तहत 2030–31 तक होगा विकास		
नई दिल्ली ।		
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन बड़े केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए 3,030 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी नई योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भय-रसायन) को हरी झंडी मिली, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को रसायन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना वर्तमान वित्त वर्ष से शुरू होकर 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। योजना की कुल लागत 3,030 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये साझा अवसररचना एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास पर और 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय पर खर्च होंगे। वैष्णव ने बताया कि ये पार्क कम से कम 2,000 एकड़ (करीब 8 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में स्थापित होंगे और प्रत्येक में 20,000 करोड़ रुपये से	20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इन पार्कों का विकास राज्यों के साथ चैलेंज रूट के तहत किया जाएगा, जहां राज्य सरकारें ग्रीनफील्ड (नई) या ब्राउनफील्ड (पुरानी) विकल्पों में से चुनाव कर सकेंगी। केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान देगी, जबकि संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपये का योगदान करना होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार यह योजना	रसायन उद्योग की समृची मूल्य शृंखला का विकास करेगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी लाएगी और घरेलू-विदेशी निवेश को बढ़ावा देगी। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और भारतीय रसायन क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। इन पार्कों में आधुनिक सुविधाएं (करीब 8 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में स्थापित होंगे और प्रत्येक में 20,000 करोड़ रुपये से

एक्सिस एमएफ के पूर्व डीलर वीरेश जोशी पर 7 साल का प्रतिबंध

30.55 करोड़ की अवैध कमाई जल्द, व्हाट्सएप चैट से खुला राज		
मुंबई ।		
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने फट-रनिंग ट्रेडिंग के गंभीर आरोपों पर ऐक्सिस म्युचुअल फंड के पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी पर सात साल के लिए प्रतिभूति बाजार में पाबंदी	लगा दी है। उन पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में सेबी ने जोशी के 20 अन्य सहयोगियों को भी 3 से 7 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, जिन पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने इस	अवैध गतिविधि के जरिये हुई अनुमानित 30.55 करोड़ रुपए की कमाई को पहले ही जब्त कर लिया है। सेबी के अंतिम आदेश के अनुसार, जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐक्सिस एमएफ के बड़े सौदों से जुड़ी गोपनीय जानकारी अपने बाहरी

कच्चे तेल और युद्ध का डर, बाजार पर भारी पड़ी भू-राजनीतिक चिंताएं
ग्लोबल अस्थिरता का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखा
भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल और विदेशी निकासी के दबाव में बाजार

शेयर बाजार साप्ताहिक समीक्षा
मुंबई ।
बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद निराशाजनक रहा, जहां प्रमुख सूचकांक लगातार पांच कारोबारी सत्रों तक गिरावट के साथ बंद हुए। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, अमेरिकी व्यापार शुल्क संबंधी नई चिंताएं और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने बाजार की

बीएनपी परिबा कार्डिफ ने इंडियाफर्ट लाइफ में खरीदी 26 फीसदी हिस्सेदारी
बैंक ऑफ बड़ौदा 65 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक
मुंबई ।
फ्रांस की बीमा कंपनी बीएनपी परिबा कार्डिफ ने निजी इकटिी फर्म वारबर्ग प्पिन्कस से इंडियाफर्ट लाइफ इश्योरेस में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इस सौदे के साथ इंडियाफर्ट लाइफ को एक नया रणनीतिक निवेशक मिल गया है, जिसका उद्देश्य कंपनी की विकास यात्रा को गति देना है। हालांकि, सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। इस अधिग्रहण के बाद इंडियाफर्ट लाइफ की शेयरधारिता में बड़ा बदलाव आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत रहेगी, जिससे वह सबसे बड़ा शेयरधारक बना रहेगा। बीएनपी परिबा कार्डिफ के पास अब 26 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नौ प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदार रहेगा। इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य बैंक ऑफ बड़ौदा के विशाल शाखा नेटवर्क, इंडियाफर्ट लाइफ की बहु-चैनल वितरण क्षमताओं और बीएनपी परिबा कार्डिफ की वैश्विक बैंकएश्योरेस विशेषज्ञता, उत्पाद नवाचार तथा बीमा क्षमताओं का लाभ उठाना है। बीएनपी परिबा कार्डिफ की सीईओ पॉलिन लेक्लेर-ग्लोरियू ने इस सौदे को उच्च संभावनाओं वाले बाजारों में मजबूत संस्थानों के साथ साझेदारी की उनकी अंतरराष्ट्रीय रणनीति का विस्तार बताया।

8वें वेतन आयोग की बैठकें अगस्त में, कर्मचारियों को मिली राहत

महत्वपूर्ण बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त को आयोजित की जाएंगी
नई दिल्ली ।
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आयोग ने दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों के साथ आगामी बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये महत्वपूर्ण बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त, 2026 के आयोजित की जाएंगी, जिनमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन से संबंधित

विभिन्न सुझावों पर गहन चर्चा की जाएगी। इस घोषणा से देश के लगभग 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिली है, जो लंबे समय से आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने उन सभी कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों को एक और अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने पूर्व में अपना मेमोरेंडम जमा कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश अभी तक आयोग के साथ उनकी बैठक नहीं हो पाई थी। ऐसे संगठन इन आगामी बैठकों में शामिल होने के लिए 31 जुलाई, 2026 तक	ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उन्हें अपनी मेमो आईडी के साथ अपॉइंटमेंट की मांग करनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर सीमित विचार किया जाएगा, इसलिए सभी संगठनों को निर्धारित तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करना है। इस
--	---

जम्मू कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कठुआ ग्रिड स्टेशन के उन्नयन के लिए 15.22 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी, जिसमें बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने पर जोर दिया गया है। प्रवक्ता के अनुसार इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य कठुआ ग्रिड स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करना और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना है। यह पहल विशेष रूप से क्षेत्र में लगातार	बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पारेषण नेटवर्क को मजबूत करेगी और उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय विद्युत अवसरचना उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों का मानना ​​है कि इस उन्नयन से पारेषण प्रणाली की विश्वसनीयता और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही, यह प्रणाली पर पड़ने वाले अधिक दबाव को कम करने में भी सहायक होगा। इसका सीधा लाभ कठुआ और आसपास के क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके लिए अब बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
--	--

श्रीराम फाइनेंस का मुनाफा पहली तिमाही में 60 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई ।		
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में 60 प्रतिशत बढ़कर 3,453 करोड़ रुपये रहा।	मुख्य रूप से आय में वृद्धि से लाभ बढ़ा है।	श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के एक कार्यकारी एे धिकारी ने कहा कि शुद्ध ब्याज आय 33.67

तक संसेक्स 442.93 अंक (और निफ्टी 95.80 अंक की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। मंगलवार को बाजार ने एक सपाट शुरुआत की, लेकिन वैश्विक अस्थिरता के कारण यह भी लाल निशान में बंद हुआ। संसेक्स 238.41 अंक और निफ्टी 50.80 अंक नीचे आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और इंफोसिस जैसे दिग्गजों के शेयरों में 2 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। हालांकि, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो सूचकांकों में कुछ हद तक बढ़त दर्ज कर थोड़ी राहत दी। बुधवार को गिरावट का सिलसिला और तेज हो गया, जो लगातार तीसरा कारोबारी सत्र था। कच्चे तेल के दामों में तेज उछाल और बैंक शेयरों में भारी बिकवाली इसकी मुख्य वजह रही। बीएसई संसेक्स	715.06 अंक और एनएसई निफ्टी 191.45 अंक की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की। ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमलों की खबरों से कच्चे तेल की कीमतों में और उछाल आया, जिससे निवेशकों की धारणा कमजोर बनी रही। संसेक्स 363.66 अंक गिरकर 76,391.39 पर और निफ्टी 126.66 अंक के नुकसान के साथ 23,869.60 के स्तर पर बंद हुआ। सप्ताह का अंत भी गिरावट के साथ हुआ। शुक्रवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में संसेक्स और निफ्टी को नुकसान हुआ। शुरुआती कारोबार में तो संसेक्स 700 अंक से ज्यादा टूट गया था, हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी हुई।
---	--

बच्चों की दवा कंपनी रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित

नई दिल्ली ।	एफएसएसआई ने तत्काल प्रभाव से उत्पादन रोकने और सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई कार्रवाई की चेतावनी दी है। एफएसएसआई के निरीक्षण दल ने रेहान हेल्थकेयर की फैक्ट्री में अत्यधिक अस्वच्छ और दूषित वातावरण पाया। पूरे परिसर में गंदगी, कीड़े-मकौड़ों का प्रकोप और साफ-सफाई के बुनियादी मानकों की घोर अनदेखी उजागर हुई। कंपनी को खाद्य सुरक्षा अनुपालन में केवल 12 प्रतिशत	अंक मिले, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अधिकारियों ने विनिर्माण इकाई के नीचे गंदगी मोटी परतें और कच्चे माल के भंडारण क्षेत्रों में भी अत्यधिक अव्यवस्था पाई, जिससे उत्पादों में संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। निरीक्षण में अपायपूर्ण भंडारण, सीमित कार्यस्थल, खराब वेंटिलेशन और पकड़ा व्यवस्था जैसी सी अन्य महत्वपूर्ण कमियां भी सामने आईं। फैक्ट्री में मकड़ी के जाले, फफूंदी, मक्खियां और खुले में पड़ा कचरा	आम बात थी। नियामक ने इस स्थिति को विशेष रूप से खतरनाक माना, क्योंकि यह इकाई बच्चों द्वारा उपभोग किए जाने वाले हाई रिस्क हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएटिकल्स बनाती है। ऐसी अव्यवस्था परिस्थितियों सीधे तौर पर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरों में डाल सकती थी। एफएसएसआई ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
--------------------	---	--	--

प्रक्रिया के तहत आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और फेडरेशनों से सुझाव एकत्र कर रहा है। दिल्ली में होने वाली ये बैठकें इसी व्यापक विचार-विमर्श प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहाँ कर्मचारी संगठन सीधे आयोग के प्रस्तुत कर सकेंगे। इन्हीं सुझावों के अध्ययन के बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, और इन्हीं के आधार पर भविष्य के नए वेतनमान व अन्य लाभ तय होंगे।	कठुआ को मिलेगी मजबूत बिजली, ग्रिड उन्नयन को 15.22 करोड़ मंजूर
--	--

कठुआ को मिलेगी मजबूत बिजली, ग्रिड उन्नयन को 15.22 करोड़ मंजूर

क्षेत्र में मिलेगी विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कठुआ ग्रिड स्टेशन के उन्नयन के लिए 15.22 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की

बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पारेषण नेटवर्क को मजबूत करेगी और उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय विद्युत अवसरचना उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस उन्नयन से पारेषण प्रणाली की विश्वसनीयता और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

जम्मू कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कठुआ ग्रिड स्टेशन के उन्नयन के लिए 15.22 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी, जिसमें बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने पर जोर दिया गया है। प्रवक्ता के अनुसार इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य कठुआ ग्रिड स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करना और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना है। यह पहल विशेष रूप से क्षेत्र में लगातार	बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पारेषण नेटवर्क को मजबूत करेगी और उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय विद्युत अवसरचना उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों का मानना ​​है कि इस उन्नयन से पारेषण प्रणाली की विश्वसनीयता और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही, यह प्रणाली पर पड़ने वाले अधिक दबाव को कम करने में भी सहायक होगा। इसका सीधा लाभ कठुआ और आसपास के क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके लिए अब बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
--	--

श्रीराम फाइनेंस का मुनाफा पहली तिमाही में 60 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में 60 प्रतिशत बढ़कर 3,453 करोड़ रुपये रहा।

मुख्य रूप से आय में वृद्धि से लाभ बढ़ा है।

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के एक कार्यकारी एे अधिकारी ने कहा कि शुद्ध ब्याज आय 33.67

प्रतिशत बढ़कर 8,056 करोड़ रुपये होने और शुद्ध ब्याज मार्जिन के पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 8.11 प्रतिशत से बढ़कर 9.04 प्रतिशत होने से मुनाफे में वृद्धि हुई।

उन्होंने कहा कि जापान के एमयूएफजी द्वारा 4.4 अरब डॉलर में कंपनी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने से भी शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़ाने में मदद मिली।

मारुति ने नई कॉम्पैक्ट एसयूवी से मचाई हलचल, कीमत 7.40 लाख से शुरू

नया 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रीमियम इंटीरियर और उन्नत सुरक्षा फीचर्स के साथ हुई एंट्री

नई दिल्ली ।

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा 2026 फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। यह नया मॉडल कई बड़े बदलावों के साथ आया है, जिसमें एक शक्तिशाली टर्बो पेट्रोल इंजन, आकर्षक डिज़ाइन और प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये तय की गई है, जो इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बिल्कुल नया 1.0 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 108 बीएचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह नया पावरट्रेन ड्राइविंग अनुभव को और बेहतर बनाएगा। डिज़ाइन की बात करें तो, नई ब्रेजा में नया फ्रंट ग्रिल, बदले हुए बंपर और नए 16 इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलते हैं, जो इसे एक फेश लुक देते हैं। यह विवेक्षिय अंरेंज और लस्टूस केज जैसे दो नए आकर्षक रंगों में भी उपलब्ध होगा। इंटीरियर में ब्लैक और ब्राउन थीम के साथ ग्लांस ब्लैक फिनिश दी गई है। इसमें अब बढ़ा 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एयर च्युरीफायर और वायरलेस चार्जर जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं, जो केबिन को अधिक आरामदायक और हाई-टेक बनाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी ब्रेजा अब और मजबूत हुई है।

बच्चों की दवा कंपनी रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित

अंक मिले, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अधिकारियों ने विनिर्माण टैंकों के नीचे गंदगी की मोटी परतें और कच्चे माल के भंडारण क्षेत्रों में भी अत्यधिक अस्वच्छता पाई, जिससे उत्पादों में संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। निरीक्षण में अपर्याप्त भंडारण, सीमित कार्यस्थल, खराब वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था जैसी अन्य महत्वपूर्ण कमियां भी सामने आईं। फैक्ट्री में मकड़ी के जाले, फफूंदी, मक्खियां और खुले में पड़ा कचरा	आम बात थी। नियामक ने इस स्थिति को विशेष रूप से खतरनाक माना, क्योंकि यह इकाई बच्चों द्वारा उपभोग किए जाने वाले हाई रिस्क हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है। ऐसी अस्वच्छ परिस्थितियों सीधे तौर पर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरों में डाल सकती थीं। एफएसएसआई ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
--	--

एचडीएफसी बैंक पर अमेरिकी जांच का साया, शेयरों में गिरावट जारी

मुंबई ।

अमेरिका की तीन प्रमुख लॉ फर्मों ने एचडीएफसी बैंक के खिलाफ संभावित संघीय प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद बैंक के शेयरों में 1 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। तिमाही नतीजों के बाद से पिछले पांच कारोबारी सत्रों में शेयर लगभग 10 फीसदी गिर चुके हैं, जिसने निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह सात महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को कथित तौर पर किए गए 45 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ी है। आरोप है कि बड़े डिपॉजिट प्राप्त करने के लिए दी गई अतिरिक्त ब्याज राशि को कथित तौर पर विपणन खर्च

के रूप में दर्ज किया गया था। इस राशि को फिर चार स्थानीय वेंडरों के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों पर खर्च दिखाया गया।

अमेरिकी लॉ फर्मों ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह मामला सामूहिक मुकदमे का रूप लेगा या नहीं। वे उन निवेशकों से जानकारी जुटा रही हैं, जिन्हें बैंक के शेयरों में आई गिरावट से नुकसान हुआ है। हालांकि, एचडीएफसी बैंक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बैंक का कहना है कि उसके सभी लेवनें निर्वारित नियमों और एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के तहत किए जाते हैं, और किसी भी अनियमितता के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।

ऋडिट कार्ड खर्च 2 लाख करोड़ के पार, लगातार दूसरे महीने उछाल

मुंबई।

भारतीय उपभोक्ताओं ने ऋडिट कार्ड के जरिए खर्च करने की अपनी आदत को जून में भी बरकरार रखा है, लगातार दूसरे महीने खर्च का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के निशान को पार कर गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जून में ऋडिट कार्ड से कुल 2.01 लाख करोड़ रुपए का व्यय दर्ज किया गया, जो पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 9.8 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि है। हालांकि, यह मई के 2.02

लाख करोड़ रुपए के मुकाबले मामूली रूप से कम रहा। ऋडिट कार्ड खर्च में प्रमुख खिलाड़ियों में एचडीएफसी बैंक और एसबीआई कार्ड का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा। एचडीएफसी बैंक ने 16.2 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी के साथ 59,432 करोड़ रुपए का खर्च दर्ज किया, जबकि एसबीआई कार्ड का खर्च 34.4 फीसदी बढ़कर 41,077 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक के ऋडिट कार्ड खर्च में 5.2 फीसदी की सालाना गिरावट दर्ज की गई और यह 31,410.9 करोड़ रुपए रहा।

जीपी पेट्रोलियम्स का मुनाफा पहली तिमाही में तीन गुना होकर 20.6 करोड़ पहुंचा

मुंबई ।

लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी जीपी पेट्रोलियम्स लिमिटेड (जीपीपीएल) का मुनाफा (पीएटी) चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में तीन गुना से अधिक होकर 20.6 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 6.4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 230.3 करोड़ रुपये हो गई, जो 2025-26 की समान तिमाही में 158.2 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कर पूर्व आय करीब तीन गुना होकर 29.2 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 10 करोड़ रुपये थी। जीपी पेट्रोलियम्स के प्रवक्ता ने कहा कि बेहतर परिचालन मार्जिन, उत्पाद मिश्रण में सुधार और परिचालन दक्षता पर लगातार ध्यान देने के साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में मजबूत शुरुआत की है।

सीडब्ल्यूजी 2026:

ग्लासगो, एजेंसी। भारत के बॉक्सर जादुमनी सिंह मंडेनगबाम ने कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 का आगाज दमदार प्रदर्शन के साथ किया है। जादुमनी ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्कॉटलैंड के एरन कलन को 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। ग्लासगो के एसईसी हॉल में खेले गए इस मुकाबले में जादुमनी शुरू से आखिर तक विपक्षी बॉक्सर पर पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने तेज पंच, सटीक निशाने और मजबूत डिफेंस के दम पर अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरे मैच में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी पांच जर्जों ने हर राउंड में जादुमनी को विजेता माना और उन्हें 30-27 का एक जैसा स्कोर दिया।

घरेलू दर्शकों के समर्थन के बावजूद स्कॉटलैंड के एरन कलन भारतीय खिलाड़ी की गति और रणनीति के आगे बेबस नजर आए।

विराट कोहली से मेरा कोई झगड़ा नहीं...

● ट्रेविस हेड ने IPL विवाद पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, ट्रेलिंग पर भी छलका दर्द

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली के साथ विवाद और उसके बाद हुई सोशल मीडिया ट्रेलिंग पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। हेड ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बाद उनके और विराट कोहली के रिश्तों में खटास आ गई थी. दरअसल, मैच खत्म होने के बाद कैमरे में एक ऐसा दृश्य कैद हुआ था,

जिसमें देखा गया कि विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों



खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव की खबरें तेजी से फैल गई. हालांकि अब हेड ने खुद इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. कोड स्पोर्ट्स से बातचीत में ट्रेड ने कहा कि विराट कोहली के साथ उनके रिश्ते सामान्य हैं और किसी तरह के विवाद की बात पूरी तरह बेबुनियाद है. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि पैच-अप करने जैसा कुछ है. ऐसी कोई बात ही नहीं है. टूर्नामेंट जैसा चला, वैसा ही सब कुछ हुआ. इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी.' हेड के इस बयान के बाद विराट और उनके बीच विवाद की सभी अटकलों पर विराम लग गया है. हेड ने बताया कि मैदान पर होने वाली घटनाओं को वह एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर संभाल लेते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर उनके परिवार को निशाना बनाया गया तो स्थिति काफी अलग हो गई.

ट्रेविस हेड का दर्द छलक पड़ा

उन्होंने कहा, 'जेसिका और मैं चीजों को सही नजरिए से देखते हैं. हम जानते हैं कि यह उसी दुनिया का हिस्सा है, जिसमें हम रहते हैं. लेकिन असली पेशेवानी तब हुई, जब मामला परिवार के दूसरे सदस्यों तक पहुंच गया. वे लोग ऐसी चीजें देखने के आदी नहीं हैं.' विवाद के दौरान ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका हेड को भी सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक संदेश मिले थे. ट्रेविस हेड ने कहा कि उनकी पत्नी ने पूरे मामले को बेहद परिपक्वता के साथ संभाला. उन्होंने कहा, 'कुछ दिनों बाद लोग सब भूल जाते हैं. जेसिका ने इस पूरे मामले को शानदार तरीके से संभाला. असली चुनौती यह होती है कि परिवार के बाकी लोग इन चीजों को किस तरह लेते हैं.' हेड ने साफ संकेत दिया कि खिलाड़ियों की आलोचना खेल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उनके परिवार को सोशल मीडिया पर निशाना बनाना सही नहीं है.

जादुमनी का दमदार आगाज

► 5-0 से जीत दर्ज कर बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह



भारतीय बॉक्सर के एक के बाद एक पंचों का एरन कलन के पास कोई जवाब नहीं था। इस जीत के साथ जादुमनी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब 26 जुलाई को उनका मुकाबला पाकिस्तान के रहमान से होगा। जादुमनी अगर

पाकिस्तानी बॉक्सर के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं, तो वह क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लेंगे। जादुमनी को भारत की ओर से पदक का बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है।

जादुमनी की इस जीत से भारतीय बॉक्सिंग टीम ने प्रतियोगिता में मजबूत शुरुआत की है। भारतीय दल इस बार ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा है। हालांकि, ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस बार बैडमिंटन, रसलिंग, हॉकी, क्रिकेट और शूटिंग को शामिल नहीं किया गया है। इन खेलों में पिछले बार भारत ने कई पदक

अपने नाम किए थे। इससे पहले, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरोगोहेन ने बिना रिंग में उतरे ही बॉक्सिंग में भारत के लिए पहला पदक पक्का कर लिया था, क्योंकि उन्हें पहले राउंड में 'बाय' मिला और वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। नियमों के अनुसार, कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में हार के बावजूद खिलाड़ी को कांस्य पदक दिया जाता है। लवलीना 31 जुलाई को पहली बार रिंग में नजर आएंगी और उनका मुकाबला टाफाकी से होगा। लवलीना अगर टाफाकी के खिलाफ जीत दर्ज करने में कामयाब रहती हैं, तो उनका कम से कम रजत पदक पक्का हो जाएगा।

सीडब्ल्यूजी: डे-2

भारत को पहला पदक, झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता कांस्य

ग्लासगो, एजेंसी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। अन्य खेलों में देश के खिलाड़ियों का हाल कैसा रहा? पैरा तैराकी समेत अन्य खेलों में किन भारतीय खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया? कौन नजदीकी अंतर से पदक से चूक गए? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का दूसरा दिन फिलहाल जारी है। पैरा तैराकी और पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत को निराशा मिली है।

पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत पदक लाने के करीब था, लेकिन अंत में पिछड़ गया। वहीं, पैरा तैराकी में बुडिगिना काफी करीब से कांस्य अपने नाम नहीं कर सके। आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल के दूसरे दिन क्या-क्या हुआ? ग्लासगो में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों



में भारत के पदक का खेल दिया है। पुरुष हेवीवेट के फाइनल में झंडू ने 130.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। झंडू ग्रुप बी में शीर्ष पर थे और एक समय स्वर्ण पदक जीतने के करीब थे, लेकिन नाइजीरिया के रिलुवान इदरिस और इंग्लैंड के मैथ्यू हाडिंग ने उन्हें तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इदरिस ने 132.8 अंकों के साथ स्वर्ण और हाडिंग ने 131 अंक के साथ रजत अपने नाम किया। भारत के एक अन्य पैरा पावरलिफ्टर सुधीर 114.1 अंक के साथ छठे स्थान पर रहे।

‘माइकल फेलप्स’, चाड ले क्लोस बने इतिहास के सबसे सफल पुरुष एथलीट



ग्लासगो, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तैराक चाड ले क्लोस कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास के सबसे सफल पुरुष एथलीट बन गए हैं। ग्लासगो में हो रहे गेम्स के दूसरे दिन पुरुषों की 4×100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही वह कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास के सबसे ज्यादा पदक

जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 34 साल के क्लोस ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया था। वह 5वीं बार गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के दिग्गज स्विमर माइकल फेलप्स के नाम है।

चाड ले क्लोस के 19 मेडल हुए

ब्रॉज मेडल के साथ ही चाड ले क्लोस के करियर में कॉमनवेल्थ गेम्स पदकों की संख्या 19 हो गई है। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के निशानेबाज फिल एडम्स और इंग्लैंड के माइक गॉल्ट को पीछे छोड़ दिया है। दोनों ने ही 19-19 मेडल जीते थे। रिकॉर्ड बनाने के बाद भावुक ले क्लोस ने कहा- मुझे ब्रॉन्ज मेडल पर नहीं गोल्ड मेडल पर रोना चाहिए था, लेकिन सच कहूं तो यह उपलब्धि मेरे लिए दुनिया के बराबर है।

वेस्टइंडीज की टीम में इस ‘मिस्ट्री स्पिनर’ की एंट्री



नई दिल्ली, एजेंसी। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. यह सीरीज 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएगी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी. ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम है. श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में 1-0 से टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है. अनुभवी ऑलराउंडर रोस्टन चेज विंडीज की टीम की कमान संभालते रहेंगे. उधर बाएं हाथ के स्पिनर जोशुआ बिशप को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया है. 26 साल के बिशप का घरेलू रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है. उन्होंने सिर्फ 25 फर्स्ट क्लास मैचों में 23.90 की औसत से 116 विकेट झटके हैं. वहीं उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचों में 30.76 के एवरेज से 1046 रन बनाए हैं. बिशप ने 54 लिस्ट-ए मैचों में 79 और 16 टी20 मुकाबलों में 12 विकेट भी चटकाए हैं.

मैकेजी की टीम में वापसी: 25 वर्षीय ओपनिंग बल्लेबाज किर्क मैकेजी की टेस्ट टीम में वापसी हुई है. उन्होंने आखिरी टेस्ट 2024 में इंग्लैंड दौरे पर खेला था .मैकेजी ने वेस्टइंडीज चैंपियनशिप के हालिया सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने छह पारियों में 323 रन बनाए और उनका औसत 64.60 रहा. शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टीम में वापसी की है.

मैं गर्व के साथ विदा ले रहा हूं

कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और देश के सबसे सफल डिफेंडों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ओटामेंडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर लिखा, 'आज मुझे अपने पूरे करियर के सबसे मुश्किल शब्द लिखने पड़ रहे हैं। मैंने बहुत कम उम्र से ही अर्जेंटीना की नेशनल टीम की जर्सी पहनते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इस अनुभवी सेंटर-बैक खिलाड़ी ने 17 साल से ज्यादा समय तक अर्जेंटीना की ओर से खेलने के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की है। ओटामेंडी ने अर्जेंटीना के लिए 139 मैच खेले और फीफा वर्ल्ड कप तथा दो कोपा अमेरिका खिताब जीते। उन्होंने अपने विदाई संदेश को अपने करियर का सबसे मुश्किल पल बताया। अर्जेंटीना की 'गोल्डन जेनरेशन' के अहम खिलाड़ी ओटामेंडी ने चार फीफा वर्ल्ड

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज का दिल्ली में आयोजन!

नई दिल्ली, एजेंसी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सितंबर में वह नई दिल्ली में भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार है। हालांकि, बांग्लादेश और भारत के बीच सीरीज पर अभी असमंजस जारी है।

फिलहाल अफगानिस्तान की मेजबानी में दिल्ली में होने वाली सीरीज की तारीखें 13, 15 और 17 सितंबर बताई गई हैं। मगर भारत और बांग्लादेश सीरीज के चलते इसकी तारीखें बदल सकती



हैं, मगर सीरीज होना पक्का है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच छह मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज (तीन टी20 और तीन वनडे) की उम्मीदें अभी बरकरार

● तारीखों में हो सकता है बदलाव

हैं। शुक्रवार को यह खबर सामने आई है कि भारतीय सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें BRICS सम्मेलन (जो सितंबर में होना है) के लिए आमंत्रित किया है। इसके बाद उम्मीदें हैं कि दोनों क्रिकेट बोर्ड और सरकारों के बीच संबंध फिर पुराने जैसे हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि वह भारत के खिलाफ 1 से 13 सितंबर तक

सीरीज की मेजबानी कर सकती है। इसी कारण भारत और अफगानिस्तान सीरीज की तारीखें थोड़ी बदल सकती हैं। क्रिकबज ने पहले इस बात की जानकारी दी थी कि बांग्लादेश बोर्ड के द्वारा टी20 सीरीज के लिए अभी EoI दस्तावेज नहीं जारी किए गए हैं। पहले सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों के कारण भारत के बांग्लादेश को आगे बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई थी।

सबसे तेज प्रयागराज, मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी संपादक हनुमान प्रसाद शुक्ल द्वारा विपिन इंटरप्राइजेस 1/6सी/1 मास्टर जर्बुल हसन रोड़, कटरा, प्रयागराज से मुद्रित कराकर, करीमुददीनपुर पोस्ट अटरामपुर नवाबगंज प्रयागराज से प्रकाशित। मो नं. 9452842169। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आ.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद का निपटारा इलाहाबाद न्यायालय में होगा। आपत्तियां एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकार की जाएंगी। समाचार पत्र की जिम्मेदारी लेखक व संवाददाता की होगी